



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2014/वैशाख 29, 1936

No. 143]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2014/VAISAKHA 29, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 13 मई, 2014

सं. टीएमपी/62/2009-पीपीटी.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, पारादीप पत्तन न्यास के दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/62/2009-पीपीटी

कोरम :

- (i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)
(ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(अप्रैल 2014 के 4थें दिन पारित)

यह मामला पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से सम्बंधित है।

2. पीपीटी का मौजूदा दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएमपी/62/2009-पीपीटी, दिनांक 25 मार्च, 2011, जिसे 23 मई, 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 तक निर्धारित करता है। इस प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 10 जनवरी, 2014 द्वारा पीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता को आगे 31 मार्च, 2014 तक विस्तारित किया था।

3. पीपीटी ने मौजूदा दरमान के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दिनांक 27 अगस्त, 2012 को दाखिल किया गया था जिसे प्रशुल्क मामला रूप में पंजीकृत किया गया था और विचार-विमर्श के लिए लिया गया था। प्रस्ताव की आंतरिक संवीक्षा की गई है और इस मामले में संयुक्त सुनवाई 25 फरवरी, 2013 को आयोजित की गई थी।

4.1. जब इस प्राधिकरण के अंतिम विचार के लिए मामला तैयार किया जा रहा था, पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 द्वारा निवेदन किया था कि वित्तीय वर्ष 2012-13 पहले ही समाप्त हो चुका है और वर्ष 2012-13 के लिए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं जिनपर विचार किया जा सकता है क्योंकि प्रहस्तित किए जाने के लिए अनुमानित कार्गो मिश्रण में बदलाव किया गया है और तेल कार्गो में काफी वृद्धि की गई है। इसके अलावा, 12 अक्टूबर, 2013 को सघन चक्रवात की वजह से, पत्तन को उसकी सम्पत्तियों का नुकसान हुआ है जिसका अनुमान रु. 82.71 करोड़ है। पीपीटी ने नुकसानों की भरपाई के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। परन्तु, यदि अनुरोध पर विचार नहीं किया जाता है, तो पीपीटी को अपने आंतरिक संसाधनों से पुनर्निर्माण की लागत को पूरा करना होगा जिससे इसके आंतरिक संसाधनों पर प्रभाव पड़ेगा।

4.2. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, पीपीटी ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए संशोधित प्रस्ताव जमा करने के लिए तीन माह के समय की मांग की थी और मौजूदा दरमान के अनुसार प्रशुल्क की लेवी की गणना करने के लिए अनुरोध किया था। पीपीटी द्वारा उल्लिखित कारणों से, इसे अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 31 जनवरी, 2014 तक का समय दिया गया था। चूंकि प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए पीपीटी को हमारे पत्र दिनांक 17 फरवरी, 2014 द्वारा अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए अनुस्मरण करवाया गया था। चूंकि पीपीटी ने जवाब नहीं दिया था, उसके उसका संशोधित प्रस्ताव तत्काल दाखिल करने के लिए अनुस्मरण करवाया जा रहा है।

5. यह स्वीकार करते हुए कि पीपीटी को अभी अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करना है, पीपीटी द्वारा दाखिल (किए जाने वाले) संशोधित प्रस्ताव की प्राप्ति के बाद अंतिम विचार करने में समय लगेगा। अतः, यह प्राधिकरण पीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता को इसकी समाप्ति की तारीख से 30 जून, 2014 अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख, जो भी पहले हो, तक विस्तारित किया जाता है।

6. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष 1 अप्रैल, 2013 के बाद प्रोद्भूत होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष अगले चक्र के लिए निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./143/2014]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 13th May, 2014

No. TAMP/62/2009-PPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/62/2009-PPT

QUORUM

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 4th day of April, 2014)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust (PPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the PPT was last approved by this Authority *vide* Order No. TAMP/62/2009-PPT dated 25 March, 2011 which was notified in the Gazette of India on 23 May, 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March, 2013. This Authority has further extended the validity of the existing SOR of PPT till 31 March, 2014 *vide* its Order dated 10 January, 2014.

3. The PPT has filed its proposal for revision of the existing SOR on 27 August, 2012 which was registered as tariff case and taken on consultation. The proposal has been internally scrutinized and joint hearing in this case was held on 25 February, 2013.

4.1. When the case was being firmed up for final consideration of this Authority, the PPT, *vide* its communication dated 30 October, 2013, submitted that as the financial year 2012-13 was already over and the actual figures for the year 2012-13 are available which may have to be considered since the cargo mix estimated to be handled has undergone a change and the oil cargo has increased substantially. Moreover, due to severe cyclone on 12 October, 2013, port has suffered damages to its properties which is estimated to be around ₹ 82.71 crores. The PPT has stated that if its request to Government of India for a grant to restore the damages caused is not considered, the PPT will have to meet the restoration cost from its internal resources which will affect its internal resources.

4.2. In view of the above position, the PPT has sought three months' time to submit a revised proposal for general revision of its SOR and has requested for continuation of levy of tariff as per existing SOR. For the reasons stated by PPT, it was allowed time till 31 January, 2014 to file its revised proposal. Since the proposal was not received, the PPT was reminded to file its revised proposal *vide* our letter dated 17 February, 2014. Since the PPT has not responded, it is being reminded to file its revised proposal immediately.

5. Recognizing that the PPT is yet to file its revised proposal it will take time for the case to mature for final consideration after receipt of the revised proposal (to be) filed by the PPT. This Authority, therefore, extends the validity of the existing SOR of the PPT from the date of its expiry till 30 June, 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

6. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return accrues to the PPT post 1 April, 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be fully adjusted in the tariff to be fixed for the next cycle.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/2014]